

# राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति

## National Farmers' Coordination Committee

Email : [kisansamanvay.india@gmail.com](mailto:kisansamanvay.india@gmail.com)



Date : 19/03/2017

प्रतिष्ठा में,  
माननीय प्रधानमंत्री जी,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : किसान और किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु किसानों द्वारा तैयार और पारित कृषि नीति लागू करने के लिये रा.कि.स.स. के प्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक करने हेतु प्रतिवेदन।

माननीय प्रधानमंत्री जी,

राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के आगरा सम्मेलन में किसान की कृषि नीति लागू करने के लिये पारित यह पत्र देश के किसान और किसान संघटनाओं के सभी सहभागी संघटनाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित कर आपको भेजा जा रहा है। आशा करते हैं की आप इस पत्र पर गंभीरता से विचार कर उसे लागू करने के उपायों पर चर्चा हेतु संवाद बैठक करेंगे। हम चाहते हैं की संवाद के माध्यम से किसानों की जटील समस्याओं का समाधान हो। इसलिये पत्र में रखे मुद्दों पर विस्तार से संवाद के लिये सरकार और रा.कि.स.स. के प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित की जाए ताकी सरकार द्वारा इन मुद्दों पर ठोस और तत्काल निर्णय किया जा सके। हम अपने तरफ से इन मुद्दों पर देश भर में किसानों के बीच जाकर जागरण का कार्य करेंगे और उन्हें एकजुट करेंगे ताकी आपको निर्णय लेने में अनुकूलता प्रदान की जा सके।

हम सब इस बात पर एकमत हैं कि, देश में किसानों की हालत बहुत गंभीर बनी है। वह दयनीय और दरिद्र जीवन जी रहा है। अगर सरकारी रिपोर्ट सही है तो ग्रामीण भारत के 95 प्रतिशत किसान गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। किसान परिवार की औसत मासिक आय 6426 रु. है; जिसमें किसान के लिये अपने परिवार का पोषण संभव नहीं है। हर किसान पर औसत 47 हजार रुपयों का कर्ज है। किसान परिवारों में हर साल 63 हजार से अधिक और प्रतिदिन 174 आत्महत्याएं हो रही हैं। जो जी रहे हैं वह भी कंगाली की जिन्दगी जी रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा की गयी हैं की किसान को खेती छोड़कर/बेचकर पलायन करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। गाव में आमदनी के श्रोत समाप्त किये गये हैं। खेती पुरक ग्रामीण रोजगार के सभी साधन पहले ही साजिषपूर्ण तरीके से खतम किये गये। अब खेती भी किसानों से छिनी जा रही है। खेती की जमीन पर गैर कृषि कार्य के लिये बड़े पैमाने पर आक्रमण हो रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के कुल 14 करोड़ हेक्टर खेती में से 5 करोड़ हेक्टर खेती कम हुयी है और यह खेती की लूट लगातार बढ़ रही है।

आज तक सरकारें कृषि में उत्पादन केन्द्रित नीतियां अपनाती आयी हैं। उससे थोडा बहुत उत्पादन बढ़ा लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। आज की किसान की हालत स्वयं इसका साक्ष्य दे रही है। अब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं वह देश के किसानों और गावों की बरबादी की रफ्तार और तेज करने जा रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पूंजी और तकनीकी पर आधारित खेती, जीएम बीज का उपयोग, खेती का यांत्रिकीकरण, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कार्पोरेट फार्मिंग के रास्ते देश में केवल 20 प्रतिशत किसान रखने की सरकार की घोषणा और उसके लिये अपनायी जा रही नीतियों से स्पष्ट है की देश के सभी किसानों से खेती छीनकर 20 प्रतिशत कार्पोरेट किसानों के हवाले की जायेगी। जब कि यह स्पष्ट है कि औद्योगिकरण में देश के दस प्रतिशत से अधिक रोजगार देने की क्षमता नहीं है। सरकार की वे नीतियां किसानों की बरबादी के साथ साथ बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खडी करने जा रही है। किसान और गावों का भविष्य अंधकारमय करने जा रही है।

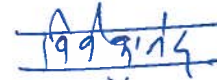
हम मानते हैं की किसान की आजकी परिस्थिति सरकारों द्वारा कापॉरेटी मुनाफे के लिये बनी किसान विरोधी नीतियों का परिणाम है। एक तरफ किसान बदहाली की जिन्दगी जी रहा है वही दुसरी तरफ देश में कापॉरेट घरानों की अमीरी में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में केवल 57 लोगोंके पास देश की आधी संपत्ति इकट्ठा हुयी है। लेकिन देश की सरकारें कापॉरेट घरानों के पक्ष में खडी होकर उन्हे लाभ पहुंचाने के लिये अपने ही किसानों को लूटने की छुट दे रही है। लोकतंत्र की इससे बडी विडंबना नही हो सकती।

अब स्थितियां असहनीय बन गयी है। इसे बदलने के लिये देश का किसान एकजुट हो रहा है। वह संवाद मे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहता है। आवश्यकता पडने पर अहिंसा के रास्ते चलकर संघर्ष के लिये तैयार है। आशा करते हैं की देश की अपनी चुनी हुयी सरकार किसानों की भावना को समझकर समाधान के लिये तुरंत कदम उठायेगी और रा.कि.स.स. के प्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक करने के लिये समय देगी। आपके विचार हेतु किसानों द्वारा पारित प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न है।

निवेदक

### राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति

अमरनाथभाई (उप्र)	ऐड.जोशी जेकब (केरल)	हेमंत कुमार(कर्णाटक)	मनोज त्यागी (उप्र)
सर्वोदय आंदोलन	समाजवादी जनपरिषद	भारतीय किसान उत्कर्ष समिति	आजादी बचाओ आंदोलन
के.व्ही. राजकुमार (तामिलनाडू)	ऐड. आराधना भार्गव (मप्र)	लिंगराज (ओरीसा)	रामपाल जाट (राज)
साउथ इंडिया गन्ना किसान संगठन	किसान संघर्ष समिति	पश्चिम ओरीसा कृषक संघटन	किसान महापंचायत
ऐड. जयन्त वर्मा (मप्र)	करणसिंग (जम्मू कश्मीर)	अविक सहा (बंगाल)	विजय जावंधिया (महा)
अखिल हिन्द अग्रगामी किसान सभा	किसान युनियन	जय किसान आंदोलन	शेतकरी संघटना
सुखदेवसिंह (पंजाब)	बलबीरसिंग राजेवाल (पंजाब)	दशरथ कुमार	विवेकानन्द माथने (महा)
खेती बाड़ी और किसान विकास मंच	भारतीय किसान युनियन	हाडोती किसान युनियन	आजादी बचाओ आंदोलन
पारसनाथ साहू (छत्ति)	मिथिलेश डांगी (झारखंड)	सत्यप्रकाश भारत (दिल्ली)	रणसिंग आर्य (उप्र)
छत्तिसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा	आजादी बचाओ आंदोलन	स्वराज अभियान	स्वराज अभियान
एड. मनिराम पुनिया (राज)	सुनिल फौजी (उ प्र)	के.व्ही. बिजू (केरल)	अरुण राय सिंघा (बंगाल)
प्रकृतीमानव हितैषी कृषि अभियान	किसान संघर्ष समिति	स्वदेशी आंदोलन	समाजवादी जनपरिषद
एम. कुरीयन (केरल)	सरस्वती केवुला (तेलंगणा)	बालकराम पटेल (छत्ति)	इरफान जाफरी(म प्र)
झिरो बजट प्राकृतिक खेती अभियान	प्राकृतिक खेती अभियान	किसान सलाहकार मंडल	किसान जगृती संगठन
दयाकिसन शर्मा (हरीयाणा)	टी. उपेन्द्र (बिहार)	हरपालसिंग राणा (दिल्ली)	उमेश तिवारी (म प्र)
हरीयाणा किसान संघर्ष समिति	सर्वोदय किसान मजदूर संघ	भारतीय किसान युनियन	रोकोटोकोठोको आंदोलन
जमील अहमद (दिल्ली)	सुरेशकुमार छिल्लर (दिल्ली)		
राष्ट्रीय किसान आधिकार आंदोलन	भारतीय किसान युनियन(अ)		



विवेकानन्द माथने  
संयोजक

राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति

संपर्क पत्ता : संयोजक, राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति, 97, जवाहर नगर, अमरावती, महाराष्ट्र. 444604

E mail : [kisansamanvay.india@gmail.com](mailto:kisansamanvay.india@gmail.com)

मोबाईल नं. 9822994821 / 9422194996